साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 11-17 दिसंबर 2023 वर्ष-9, अंक-35

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

इंदौर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर, जो खेती को देता है बढ़ावा

देश के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक एमपी में गिरा भाव

किसानों को अच्छा दाम मिले इसके लिए कोई इंतजाम नहीं

भोपाल। जागत गांव हमार

देश के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक मध्य प्रदेश में इसकी खेती करने वाले किसानों को अच्छा दाम नहीं मिल रहा है। यहां न्यूनतम दाम 2201 रुपए प्रति क्विंटल रह गया है, जो इसकी एमएसपी से काफी कम है। अधिकतम दाम 5490 जबकि औसत दाम 4664 रुपए प्रति क्विंटल रह गया है। किसानों को इतने कम दाम से परेशानी हो रही है। एक तरफ सरकार खाने वाले तेल का आयात कर रही है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के किसानों को तिलहन फसल सोयाबीन का दाम नहीं मिल रहा है। सोयाबीन का एमएसपी 4600 रुपए प्रति क्विंटल है। मध्य प्रदेश में इसका न्यूनतम दाम एमएसपी का आधा भी नहीं है। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है।

इंदौर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर

मध्य प्रदेश में इंदौर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर है, जो इसकी खेती को बढ़ावा देने का काम करता है, लेकिन इसका किसानों को अच्छा दाम मिले इसके लिए कोई खास इंतजाम नहीं दिखता है। मध्य प्रदेश के किसानों को न्यूनतम दाम सिर्फ 2200 रुपये मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने एमएसपी घोषित करते हुए बताया था कि किसानों को इसकी उत्पादन लागत 3029 रुपए प्रति क्विंटल आती है।

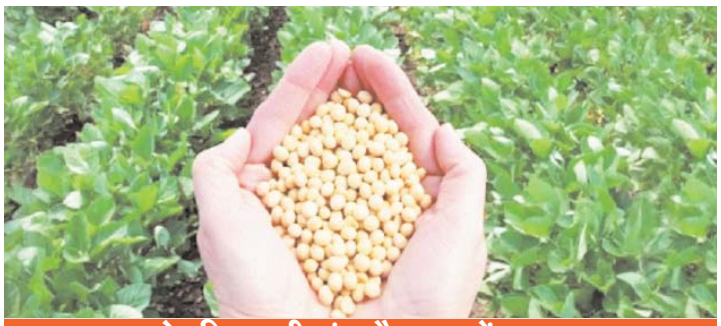

सोयामिल्क की मांग और खपत में इजाफा

इधर, सोयाबीन के इस्तेमाल से बनने वाले सोयामिल्क की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल के अनुसार मेसर्स बायो न्यूट्रिएंट्स और आईसीएआर-सीआईएई भोपाल के बीच सोयामिल्क पाउडर के प्रोडक्शन के लिए मेंबरेस टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। भोपाल ने बेहतर कलर और रीस्ट्ररिंग क्वालिटी के साथ तत्काल सोया मिल्क पाउडर के उत्पादन के लिए प्रि या विकसित की है। इस प्रक्रिया में सोया मिल्क को स्प्रे से सुखाना और लिक्विड बेड ड्रायर में पाउडर को इकट्ठा करना शामिल है। रिसर्च रिजल्ट्स के आधार पर प्रॉसेसिंग स्टैंडर्ड को मेसर्स बायो न्यूट्रिएंट ने अपनाया है, जिससे फर्म को बेहतर गुणवत्ता वाले सोयामिल्क पाउडर का उत्पादन करने और न्यूनतम प्रॉसेस्ड प्रोटीन पाउडर के रूप में बेहतर बाजार मांग दिखी है।

सरकार ने मटर का आयात खोला

आम चुनाव के मौसम में सरकार ने दाल सस्ती करने की गरज से पीली मटर का आयात खोल दिया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दस साल बाद देश में पीली मटर का आयात शुरू करने के संकेत दिए। पीली मटर के आयात को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। पहले आयात शुल्क 50 प्रतिशत था जिसे अब शून्य कर दिया गया है। हालांकि अधिसूचना में न्यूनतम कीमत का बंधन छह गुना तय किया गया है। इस नोटिफिकेशन से कारोबारी और आयातक उलझ गए हैं। देश के किसानों के हितों के लिए करीब दस साल से देश में पीले मटर के आयात को अनुमति नहीं है। बीते दिनों में देश में चना दाल के दाम ऊंचे हुए थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने नैफेड के चने से दाल बनवाकर रियायती दामों पर देशभर में वितरित की थी। अब नैफेड के पास चने का स्टाक न के बराबर है। ऐसे में सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी कर मटर आयात पर लगने वाली ड्यूटी 31 मार्च 2024 तक के लिए तत्काल प्रभाव से हटा दी है।

खाद्य तेलों में योगदान | भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के अनुसार वर्तमान में सोयाबीन देश में कुल तिलहन फसलों का 42 प्रतिशत है। कुल खाद्य तेल उत्पादन में सोयाबीन का 22 प्रतिशत योगदान है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ खाद्य तेल की मांग बढ़ रही है और विभिन्न तिलहनी फसलों द्वारा 40 फीसदी मांग को पूरा किया जा रहा है। खाद्य तेलों की बाकी 60 प्रतिशत मांग आयात द्वारा पूरी की जा रही है। सोयाबीन किसानों को 2021 में 10 हजार क्विंटल तक का दाम मिला था।

लहसुन की कीमत में भी लगी आग, 250 रुपए किलो के पार

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में खाने- पीने की चीजों की कीमत में आग लगी हुई है। लहसुन के अलावा प्याज, दाल,चीनी और गेहूं, आटा और चावल भी महंगे हो गए हैं। खास कर प्याज की बढ़ती कीमत ने लोगों को परेशान कर दिया है। 30 से 35 रुपए किलो मिलने वाला प्याज अब 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने प्याज की निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक के लिए बैन लगा दिया। अगले साल 31 मार्च तक देश से बाहर प्याज का निर्यात नहीं किया जाएगा। इधर,लोगों को लग रहा है कि सिर्फ प्याज ही महंगा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्याज से भी ज्यादा महंगा अभी लहसुन है। रिटेल मार्केट में लहसुन 250 से 300 रुपए किलो बिक रहा है। इससे आम जनता का बजट बिगड़ गया है। लेकिन कीमतों में उछाल आने से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। लोगों का कहना है कि 250 ग्राम लहसुन के लिए उन्हें 60 से 70 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। पिछले साल मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में किसानों ने काफी अधिक रकबे में लहसुन की बोवनी की थी, लेकिन, उत्पादन अधिक होने से लहसून का भाव गिर गया था। ऐसे में किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में किसानों ने इस साल कम रकबे में लहसुन की बोवनी की।

- केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर मार्च तक लगाया प्रतिबंध
- अभी थोक मार्केट में लहसुन 180 से 220 रुपए किलो
- पिछले साल लहसुन 60 से 100 रुपए किलो बिका था

कीमतें और बढ़ेंगी

किसानों का कहना है कि आने वाले दिनों में लहसुन की कीमत में और बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि किसानों ने इस बार बहुत ही कम रकबे में लहसुन की बोवनी की है। जबकि, सर्दी बढ़ने के साथ ही इसकी मांग में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे में कीमतें अपने-आप बढ़ेंगी।

100 मिलियन यूजर्स इस्तेमाल कर रहे, गांवों में पहुंचाने पर सरकार का जोर

देश के 750 जिले और 6 लाख गांवों में पहुंची 5-जी इंटरनेट सुविधा

भोपाल। जागत गांव हमार

देशभर में 750 से ज्यादा जिले हैं और 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। इनमें से 738 जिलों में 5जी इंटरनेट सुविधा पहुंच चुकी है। सरकार का फोकस ग्रामीण इलाकों तक तेज इंटरनेट सेवाएं देने पर है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 में पहली बार टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का ग्रॉस रेवेन्यू 3 लाख करोड़ पहुंच गया है। सरकार ने लोकसभा में कहा कि भारत ने अब तक 738 जिलों और लगभग 100 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक नवीनतम दूरसंचार तकनीक के साथ दुनिया में सबसे तेज 5जी रोलआउट देखा है। संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने बताया कि 24 नवंबर 2023 तक देशभर के 738 जिलों में 5जी नेटवर्क शुरू कर दिया गया है और 5जी सेवाओं का उपयोग करने वाले लगभग 100 मिलियन ग्राहकों के साथ कुल 3,94,298 बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

दो लाख करोड़ का निवेश

संचार राज्य मंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया में सबसे तेज 5जी रोलआउट में से एक देखा है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने जुलाई-अगस्त 2022 में नीलामी के जरिए हासिल स्पेक्ट्रम के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के कमिटमेंट सहित कुल 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। सरकार तेजी से ग्रामीण इलाकों में 5जी इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने पर फोकस किए है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का वित्त वर्ष 2022-23 में पहली बार ग्रॉस रेवेन्यू 3 लाख करोड़ पहुंच गया है।

स्पेक्ट्रम बिजनेस की अनुमति

मंत्री ने कहा कि सरकार ने एजीआर की परिभाषा को तर्कसंगत बनाया है। स्पेक्ट्रम बिजनेस की अनुमति दी है। इसके अलावा 100 फीसदी डायरेक्ट फॉरेन इनवेस्टमेंट अनुमति दी है। खुली और ट्रांसपैरेंट टेंडर के जरिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम सुनिश्चित किया है। सरकार ने टेलीकॉम के बुनियादी ढांचे की तेज और आसान तैनाती के लिए भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियम में संशोधन किया है। इससे मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे पर 5जी ऑप्टिकल फाइबर केबल की तैनाती का रास्ता साफ हुआ है।

31 मार्च 2024 तक के लिए लगी रहेगी रोक, अगस्त में 40 फीसदी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी

केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए प्याज के निर्यात पर रोग लगा दी है। अगले साल 31 मार्च तक देश से प्याज का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। कहा जा रहा है कि सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगाने के लिए यह कदम उठाया है। सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से देश में प्याज का भंडारण बढ़ जाएगा, जिससे कीमतों में गिरावट आएगी। इससे प्याज फिर से एक बार अपनी पुरानी कीमतों पर पहुंच सकता है। खास बात यह है कि सरकार ने इस साल 28 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्याज निर्यात पर 800 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लागू किया था। इसका उद्देश्य भी घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता को बढ़ावा देना और उनकी कीमतों को नियंत्रित करना था। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से इसको लेकर एक अधिसूचना भी जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से प्याज के निर्यात पर 31 मार्च, 2024 तक के लिए बैन लगा दिया है। अब 31 मार्च तक दूसरे देशों में प्याज का निर्यात नहीं किया जाएगा। दरअसल, दशहरा के बाद से प्याज की कीमत में आग लगी हुई है। सितंबर महीने तक जो प्याज 30 से 35 रुपए किलो बिकता था, अब उसकी कीमत 50 से 60 रुपए हो गई है। हालांकि, केंद्र सरकार खुद भी कम कीमतों पर प्याज बेच रही है। इसके बावजूद भी कीमतों में कोई गिरावट नहीं आई है। यही वजह है कि सरकार ने देश में प्याज का भंडार बढ़ाने के लिए इसके निर्यात पर 31 मार्च तक के लिए रोक लगा दी।

इतनी बढ़ी महंगाई

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्याज की अखिल भारतीय खुदरा कीमत 29 नवंबर को 94.39 प्रतिशत बढ़कर 57.85 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जो एक साल पहले 29.76 रुपए प्रति किलोग्राम थी। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार, त्योहारी मांग और बेमौसम बारिश के चलते खरीफ सीजन में कम उत्पादन के कारण अक्टूबर की तुलना में नवंबर में प्याज और टमाटर की कीमतों में क्रमश 58 प्रतिशत और 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे आम जनता के किचन का बजट बिगड़ गया है। कई परिवारों ने तो प्याज खरीदना ही छोड़ दिया है।

और बढ़ सकती है महंगाई

पिछले कुछ महीनों से देश में खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ती ही जा रही है। चावल, दाल, गेहू और चीनी की बढ़ती कीमतों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि अगले साल अप्रैल-मई महीने में लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। अगर इन खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट नहीं आती है, तो विपक्ष इसे मुद्दा भी बना सकता है।

40 फीसदी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी

सरकार ने अगस्त में प्याज पर 40 फीसदी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। हालांकि, इसके बावजूद भी निर्यात में कोई गिरावट नहीं आई। इसके बाद निर्यात के बड़े पैमाने पर अंडर-इनवॉइसिंग ने शुल्क को कम कर दिया, जिससे सरकार को इसे खत्म करने और प्याज पर 800 डॉलर प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं, इस साल मिस्र और तुर्की जैसे प्रमुख प्याज निर्यातकों ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। पाक में प्याज का उत्पादन कम हुआ है। कहा जा रहा है कि प्याज के निर्यात पर बैन लगाने से कई देशों में इसकी कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है।

दोनों खाद ऐसी हैं जिसका अधिकांश हिस्सा विदेशों से आता है...

डीएपी खाद 20 फीसदी तक महंगी, एमओपी के भी बढ़े दाम

भोपाल। जागत गांव हमार

रबी सीजन के दौरान डीएपी खाद की महंगाई 20 परसेंट तक बढ़ गई है। यह महंगाई ऐसे वक्त में सामने आई है जब कई रबी फसलों की बोवनी और निराई-गुड़ाई का काम चल रहा है। सिंचाई भी जारी है। ऐसे में खादों की खपत बढ़ जाती है, लेकिन देश के किसान महंगी खादों से परेशान हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय खाद मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी है कि डीएपी की महंगाई इसलिए बढ़ी है क्योंकि पीछे से दाम बढ़ कर आ रहे हैं। मांडविया ने बताया है कि डीएपी और एमओपी जैसी खादों के लिए देश को आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। जिन देशों से खाद आयात होता है, उन देशों ने दाम बढ़ा दिए हैं। यही वजह है कि देश के किसानों को महंगे डीएपी से दो चार होना पड़ रहा है। खाद मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि पिछले दो हफ्तों में डीएपी के दाम में 20 परसेंट तक की बढ़ोतरी है। डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी बड़ी मात्रा में विदेशों से आयात होता है। जिन देशों से यह खाद मंगाई जाती है, उन देशों ने आपदा में अवसर तलाशते हुए डीएपी के दाम बढ़ा दिए हैं। लिहाजा भारत को डीएपी का आयात महंगा पड़ रहा ह। यही वजह है कि आयात के महंगा होने से किसानों को मिलने वाली डीएपी की बोरी भी महंगी हो रही है।

आयात पर निर्भरता

भारत में कई विदेशी खाद कंपनियां अपना बिजनेस करती हैं। ये वहीं कंपनियां हैं जिनका माल भारत में आयात होता है। इन कंपनियों पर आरोप है कि भारत में जिस वक्त खादों की मांग बढ़ती है, ठीक उसी समय जानबूझ कर महंगाई बढ़ा दी जाती है। इन कंपनियों पर डिमांड को देखते हुए दाम बढ़ाने के आरोप हैं। इन आरोपों को उस वक्त बल मिला जब खाद मंत्री मनसुख मांडविया ने खुद इन्हें लाइन हाजिर किया और दामों को लेकर सख्त चेतावनी दी। खाद मंत्री ने विदेशी कंपनियों से साफ लहजे में कहा कि कार्टेलाइजेशन से बचें और किसानों का एहतराम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मांग को देखते हुए अपने फायदो को प्राथमिकता दी जाए।

खादों का गणित

भारत में यूरिया ही एक ऐसी खाद है जिसका निर्माण बड़े स्तर पर किया जाता है। कुल मांग का तकरीबन 75-80 फीसद हिस्सा भारत अपनी बदौलत पूरा करता है। बाकी कुछ हिस्सा विदेशों से आयात की गई यूरिया से पूरा किया जाता है, लेकिन डीएपी और एमओपी के मामले में यह बात लागू नहीं होती। ये दोनों खाद ऐसी हैं जिसका अधिकांश हिस्सा विदेशों से आता है। देश की कुल मांग की आधी डीएपी खाद विदेशों से आयात की जाती है। खासकर पश्चिम एशिया के देशों और जॉर्डन से।

कंपनियों को चेतावनी

यही हाल म्यूरिएड ऑफ पोटाश यानी कि एमओपी का है। एमओपी ऐसी खाद है जो पूरी तरह से विदेशों से मंगाई जाती है। इसमें बेलारूस, कनाडा और जॉर्डन जैसे देश शामिल हैं जो भारत की मांग को पूरा करते हैं। इन देशों की कंपनियां भारत में काम करती हैं और अपना बिजनेस करती हैं। लेकिन हालिया खपत को देखते हुए कंपनियों ने डीएपी और एमओपी जैसी खादों के दाम को बढ़ा दिया है। इस बढ़ोतरी में कंपनियों का कार्टेलाइजेशन काम कर रहा है। यानी कंपनियों ने एकसाथ मिलकर पूरी तैयारी के साथ भारत में खाद महंगी की है जिसे लेकर खाद मंत्री ने चेतावनी जारी की है।

जंगली जानवरों को आने से रोकने की कवायद

बाघ प्रभावित आधा दर्जन गांवों में लगा सोलर करंट

उमरिया। जागत गांव हमार

उमरिया जिले में लगातार बढ़ते जंगली जानवरों के हमले रोकने की कवायद की जा रही है। प्रबंधन ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सटे गांव में सोलर पैनल के माध्यम से करंट फैलाने का फैसला कर लिया है। जानवर जैसे ही तार के पास पहुंचेंगे उन्हें जोर का झटका लगेगा और वे गांव की तरफ नहीं जाएंगे। उमरिया के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे आधा दर्जन गांवो में बीते नौ माह के भीतर बाघ के हमले से छह ग्रामीणों की मौत के बाद पार्क प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। पार्क प्रबंधन बाघ के हमले से प्रभावित आधा दर्जन गांवों में तारबंदी के जरिए सोलर करंट फैलाएगा। प्रबंधन का दावा है कि जैसे ही वन्य जीव फेंसिंग को लांघने की कोशिश करेगा सोलर पैनल करंट के झटके से वापस जंगल की ओर लौट जाएगा और ग्रामीणों को बाघ तेंदुआ और जंगली हाथियों के उत्पात से निजात मिलेगी। गौरतलब है कि बांधवगढ़ में बाघ, तेंदुए के अलावा वर्तमान में जंगली हाथी भी गांवों में घुसकर उत्पात मचा रहे हैं, जिसके कारण लगातार वन विभाग और ग्रामीणों के बीच द्वंद्व बढ़ रहा है। जहां हिंसक जानवर ग्रामीणों की फसल और घर तो तबाह ही करते हैं। इसके अलावा ग्रामीणों को जनहानि का भी खामियाजा उठाना पड़ रहा है। प्रबंधन की कवायद से अब ग्रामीणों को फायदा मिलेगा।

अब अर्जुन मुंडा होंगे देश के नए केंद्रीय कृषि मंत्री

भोपाल। अर्जुन मुंडा देश के नए केंद्रीय मंत्री होंगे। अर्जुन मुंडा झारखंड से हैं और भाजपा के पुराने नेता हैं। अभी हाल के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया था जिसमें वे दिमनी से विजयी हुए हैं। इसके बाद तोमर को मप्र की राजनीति में उतारने का फैसला हुआ। एक दिन पहले उन्होंने संसद से इस्तीफा दिया। इसके बाद नए कृषि मंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा के नाम का फैसला हुआ। अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसे देखते हुए मुंडा के नाम को प्रमुखता से देखा जा रहा है। तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके खूंटी लोकसभा से सांसद चुने गए अर्जुन मुंडा को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फिलहाल जनजातीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन अब उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया है।

उम्मीदों को पंख

छिंदवाड़ा जिले के एक युवा किसान आधा एकड़ खेत में पॉली हाउस बनाकर डच रोज की खेती कर रहे हैं। इससे उनको रोजाना 4 हजार रुपए का मुनाफा हो रहा है। इस युवा किसान की सफलता देखकर आसपास के किसान भी उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। जागत गांव हमार अपने इस अंक में पाठकों को मिलवा रहा है पांढुर्णा के 30 साल के धीरज घाघरे से। वे राजना गांव के रहने वाले हैं। धीरज ने पुणे से इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट से एमबीए किया है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने की जगह खेती को करियर के रूप में चुना।

गुलाब की खेती करने वाला एमबीएधारी किसान

एक दिन में कमा रहे 4000 रुपए दूसरे किसानों को भी दे रहे ट्रेनिंग

इस साल पहली बार डच रोज की खेती की है। पुणे में एमबीए के दौरान एक दिन फ्लावर्स के पॉली हाउस देखने गया था। वहीं से डच रोज की खेती करने का आइडिया आया। पहले अपने खेतों में कपास की खेती होती थी, लेकिन उससे खास इनकम नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने गांव आकर फूलों की खेती का अध्ययन शुरू किया, फिर मुझे पता चला कि गुलाब की खेती के लिए काली मिट्टी से ज्यादा लाल मिट्टी फायदेमंद होती है, इसलिए मैंने तीन एकड़ जमीन में से आधे एकड़ में लाल मिट्टी डलवाई। डच रोज की खेती शुरू कर दी। मुनाफा इतना बढ़ने लगा कि फिर कदम वापस नहीं किए।

फूलों की खेती करने के लिए पहले पॉली हाउस की जरूरत होती है, इसलिए पॉली हाउस के संबंध में जानकारी जुटाना शुरू किया। पता चला कि पॉली हाउस के लिए सरकार से सब्सिडी मिलती है। इसके बारे में और जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि डच रोज की खेती करने के लिए जमीन का समतल होना जरूरी होता है, इसलिए सबसे पहले उसे समतल कराया फिर पॉली हाउस का स्ट्रक्चर खड़ा किया।

इस दौरान देखना जरूरी होता है कि वो सीधा और बैलेंस्ड रहे, क्योंकि बैलेंस बिगड़ा तो गिरने का खतरा होता है। फिर फाउंडेशन बनाने का काम किया। जमीन में पाइप डालने के लिए 3 से 4 फीट के गड्ढे किए। खेती वाली जमीन पर पानी की निकासी का भी ध्यान देना पड़ता है। इसमें एक तरफ पाइप लगाए, जिससे पानी नीचे आ जाता है।

सरकार की तरफ से 50 फीसदी सब्सिडी मिली

पॉली हाउस में एक पेपर लगाना होता है, जो इजरायल में बनता है। इस पेपर को लगाने से हाउस के अंदर का तापमान मेंटेन रहता है। इसके बाद फिर हाउस के अंदर की जमीन तैयार की जाती है। सबसे पहले जमीन पर प्लाऊ चलाया। 30-35 ट्रॉली गोबर की खाद डाली। फिर एक बार खेत की जुताई करके रोडर वेटर चलाया। पानी से सिंचाई के बाद पौधे लगाने से पहले बेड (ड्रेन्स) बनाए। ये बेड 90-110 सेमी चौड़े और लगभग एक से डेढ़ फीट ऊंचे होते हैं। जिन्हें मिट्टी से बनाया जाता है। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 40 सेमी होती है। बेड थोड़े चौड़े रखना होते हैं, ताकि एक बेड पर पौधों की डबल लाइन लगाई जा सके। बेड बनाने में भी गोबर या ऑर्गेनिक खाद डाला जाता है। इसके बाद हाथ से एक-एक कर पौधे रोपे जाते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 15 सेमी रखी जाती है। गुलाब की इस वैरायटी के पौधे टॉप सीक्रेट किस्म के होते हैं। जिन्हें मैंने पुणे से मंगाया था। एक पौधे की कीमत 4 से 5 रुपए तक होती है। मैंने आधा एकड़ जमीन में लगभग 15 हजार पौधे रोपे हैं। एक पौधा करीब 5 साल तक उत्पादन देते हैं। एक बार तोड़ने के बाद 40 दिन बाद फिर से फूल खिल जाते हैं। पॉली हाउस बनाने समेत प्रोजेक्ट पर 30 लाख रुपए की लागत आई, जिसमें सरकार की तरफ से 50 फीसदी की सब्सिडी भी मिली।

सिंचाई के लिए लगते हैं अलग-अलग पाइप

पॉली हाउस में फूलों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो पाइप लगाए जाते हैं। एक पाइप से पौधों की जड़ों को पानी दिया जाता है। दूसरे पाइप में स्प्रिंकलर लगे होते हैं, जिससे पत्तियों और टहनियों को पानी मिलता है। पॉली हाउस के बाहर एक पानी का टैंक बनाकर उससे सप्लाई होती है। सिंचाई के समय सबसे जरूरी बात ये होती है कि कहीं पानी जरूरत से ज्यादा या कम न हो जाए, क्योंकि ज्यादा पानी से बैड टूटने का डर होता है। कम पानी से पौधे सूखने का। इसके अलावा, रोजाना फर्टिगेशन प्रोसेस चलता है। इसमें कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम और एनपीके का छिड़काव किया जाता है। इससे पौधे की हेल्थ ठीक रहती है। उसमें कीड़े लगने का खतरा भी नहीं होता।

बिक्री के लिए विदेश भी जाता है डच रोज

धीरज ने बताया कि राजना गांव के लिए गुलाब का सबसे नजदीकी मार्केट नागपुर, भोपाल और इंदौर का है। यहां गुलाब के अच्छे दाम मिलते हैं। सबसे अच्छी बात है कि भारत में गुलाब के फूलों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। जितना गुलाब उगता है, उसका अधिकतर हिस्सा यहीं खप जाता है। इसके अलावा, मंडी से डच रोज को कुछ बाहरी देश (नीदरलैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया) में भी निर्यात किया जाता है, जिससे किसान और विक्रेता अच्छा खासा मुनाफा ले पाते हैं।

बैंक से मिलती है आर्थिक सहायता

धीरज घाघरे बताते हैं कि अगर हितग्राही के पास बैंक में मोडगेज रखने के लिए प्रॉपर्टी हो, तो शर्तों के आधार कर बैंक प्रोजेक्ट फाइनेंस कर देता है। पॉली हाउस के स्ट्रक्चर निर्माण के लिए बैंक शासन द्वारा निर्धारित दर का भुगतान करता है। अगर लाभार्थी को पॉली हाउस अच्छे वेंडर से बनवाना हो, तो उसके लिए खुद का बैकअप होना चाहिए। इसके बाद जब काम शुरू हो जाता है। ध्यान से खेती की जाए, तो कुछ ही महीनों में प्रोजेक्ट का लोन चुकता हो जाता है।

पहली फसल से 20 हजार रुपए की बचत

धीरज के मुताबिक प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद करीब 4-6 महीने बाद गुलाब के पौधों में फूल आने लगते हैं। पहली फसल में इतनी आमदनी होती है कि बैंक की किस्त, लेबर चार्ज, सिंचाई का खर्च निकालने के बाद भी प्रतिमाह 20 हजार रुपए तक बचत हो जाती है।

नवंबर-दिसंबर में क्वालिटी बेहतर होने से मिलते हैं अच्छे दाम

भारतीय बाजारों में गुलाब के फूलों की मांग पूरे समय होती है। नवंबर-दिसंबर महीने में गुलाब के फूलों की क्वालिटी अच्छी होती है। इस सीजन में शादियां और त्योहार भी ज्यादा होते हैं। डच रोज का इस्तेमाल ज्यादातर सजावट और बुके के तौर पर गिफ्ट देने के लिए किया जाता है। इसी वजह से इन महीनों में गुलाब की बिक्री पर सामान्य महीनों की अपेक्षा ढाई गुना दाम ज्यादा मिलता है। गुलाब के पौधों की देखभाल बच्चों की तरह करनी पड़ती है। गुलाब के पौधे लगाने से लेकर फूल तोड़ने का काम कुशल श्रमिक द्वारा किया जाता है। छिंदवाड़ा में गुलाब की खेती करने वालों के लिए नागपुर से एग्रोनोमिक्स की विजिट करवाना ज्यादा आसान होता है। धीरज कहते हैं कि मैं गुलाब के पौधों की देखभाल के लिए प्रत्येक माह एग्रोनॉमिक्स की विजिट करवाता हूं। इनकी एक विजिट की फीस 5000 रुपए होती है। जो हर जगह की जलवायु के आधार पर वहां के पौधों का ट्रीटमेंट करते हैं।

विश्व मृदा दिवसः 5 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है और इसके मायने

हर साल 5 दिसंबर यानि के आज के दिन दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। हमारा 95 प्रतिशत भोजन मिट्टी और पानी से ही उत्पन्न होता है ऐसे में मिट्टी की खराब स्थिति के कारण मिट्टी का तेजी से कटाव हो रहा, जो दुनिया भर में एक गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा बनता जा रहा। लगभग 45 साल पहले भारत में 'मिट्टी बचाओ आंदोलन' की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों का ध्यान मृदा संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन की ओर लाना है। लगातार असंतुलित खाद-उर्वरक के प्रयोग, अत्याधिक फसल उत्पादन, जनसंख्या का दबाव, बढ़ते प्रदूषण एवं अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं के कारण मिट्टी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

स्वस्थ मिट्टी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने और मिट्टी संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन की वकालत करने के लिए विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत वर्ष 2013 से की गई थी। वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ (आईयूएसएस) द्वारा मिट्टी का जश्न मनाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस की सिफारिश की गई थी। थाईलैंड साम्राज्य के नेतृत्व में और वैश्विक मृदा भागीदारी के ढांचे के भीतर, एफएओ ने वैश्विक मृदा के रूप में डब्ल्यूएसडी की औपचारिक स्थापना का समर्थन किया है। जागरूकता बढ़ाने वाला मंच एफएओ सम्मेलन ने जून 2013 में सर्वसम्मति से विश्व मृदा दिवस का समर्थन किया और 68वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे आधिकारिक रूप से अपनाने का अनुरोध किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहले आधिकारिक रूप से विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया।

विश्व मृदा दिवस 2023 की थीम क्या है?: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व मृदा दिवस 2023 का विषय मिट्टी और पानी, जीवन का एक स्रोत पर आधारित है। हमारा 95 प्रतिशत से अधिक भोजन इन दो मूलभूत संसाधनों से उत्पन्न होता है। मिट्टी का पानी, पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र को एक साथ बांधता है। यह सहजीवी संबंध हमारी कृषि प्रणालियों की नींव है। इसमें आगे कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधि के कारण, हमारी मिट्टी खराब हो रही है, जिससे हमारे जल संसाधनों पर अत्याधिक दबाव पड़ रहा है। कटाव प्राकृतिक संतुलन को बाधित करता है, जिससे पानी की घुसपैठ और सभी प्रकार के जीवन के लिए उपलब्धता कमी हो जाती है।

इस तरह रखें मिट्टी का ध्यान: अधिक समय तक अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखा जाए। समय-समय पर मिट्टी की जाँच करायी जाए तथा जाँच के अनुसार फसल के लिए जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा का उपयोग किया जाए। अनुशंसित उर्वरकों के उपयोग से फसलों को संतुलित पोषण मिलता है, साथ ही मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहता है। खेती की लागत में कमी आती है तथा फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है।

भारत में किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाये जाते हैं, जिसमें मिट्टी में मौजूद सभी पोषक तत्वों की जानकारी किसानों को दी जाती है। जिसके आधार पर खाद-उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य दिवस पर कृषि विभाग द्वारा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण किया जाता है, साथ ही जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन कर किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए जानकारी दी जाती है।

मिट्टी को बीमार होने से बचाने के लिए ये काम है जरूरी: इस दिवस के मौके पर मृदा के स्वास्थ्य के प्रति किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है। इस दिवस के इतिहास की बात करें तो वर्ष 2002 में एक पहल के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ की ओर से विश्व मृदा दिवस मनाने की सिफारिश की गई थी। कृषि एक्सपर्ट्स के अनुसार मिट्टी खेती का एक अभिन्न हिस्सा है। मिट्टी जितनी उपजाऊ होगी, फसल उतनी ही अच्छी होगी।

विश्व मृदा दिवस मनाने का उद्देश्य किसानों को मिट्टी की महत्ता के बारे में जागरूक करना है। इस अवसर पर शिविर लगाकर किसानों को मृदा को कैसे स्वस्थ रखा जाए इसके साथ-साथ अपने खेत की मिट्टी की जांच कराने के फायदे बताए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बदलते जल -वायु परिवर्तन के कारण मिट्टी बीमार होती जा रही है, जिसके कारण मिट्टी के जैविक गुणों में कमी आने की वजह से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में गिरावट आ रही है और यह प्रदूषण का शिकार हो रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए जैविक उर्वरक का प्रयोग करें। इससे खेती की उर्वरा बनी रहती है तथा पैदावार भी अच्छी होती है। खेती में किसान भाई रासायनिक पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कम से कम करें, अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं ताकि उनकी आय भी दोगुनी हो सके।

वहीं, किसानों का मानना है कि मृदा स्वास्थ्य परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिक रसायन के प्रयोग से मृदा बंजर होती जा रही है। हमें आर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा और गुणवत्ता भी अच्छी होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार पहले के मुकाबले अब मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। इससे फसलों की पैदावार पर भी असर पड़ रहा है।

डेयरी फार्मिंग से लाभ उठाने के लिए नवजात पशुओं की देखभाल जरूरी

डॉ.संदीप नानावटी
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
पशुपालन एवं प्रबंध विभाग,
पशु चिकित्सा महाविद्यालय, महू

पशुपालकों को डेयरी फार्मिंग से पूरा लाभ उठाने के लिए नवजात बछड़ियों की उचित देखभाल व पालन-पोषण करके उनकी मृत्यु दर घटाना आवश्यक है। नवजात बछड़ियों को स्वस्थ रखने तथा उनकी मृत्यु दर कम करने के लिए काफी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर गाय व भैंसों के बच्चे जीवित नहीं रह पाते। भैंसों के तो 55 प्रतिशत बच्चों की जन्म के एक माह मे मृत्यु हो जाती है। दुधारू पशुओं के बछड़े-बछियों मे मृत्यु दर बहुत अधिक है। इसका प्रमुख कारण है। उनके पेट में गोल कृमि का संक्रमण होना।

नवजात बछड़ियों को स्वस्थ रखने तथा उनकी मृत्यु दर कम करने के लिए हमें निम्नलिखित तरीके अपनाने चाहिए-

- गाय अथवा भैंस के ब्याने के तुरन्त बाद बच्चे के नाक व मुंह से श्लेष्मा व झिल्ली को साफ कर देना चाहिए, जिससे बच्चे के शरीर में रक्त का संचार सुचारू रूप से हो सके।
- बच्चे की नाभि को ऊपर से 1/2 इंच छोडकर किसी साफ कैंची से काट देना चाहिए तथा उस पर टिंचर आयोडीन लगा दें।
- जन्म के 2 घंटे के अन्दर बच्चे को माँ का पहला दूध (खीस) अवश्य पिलाना चाहिए। खीस एक प्रकार का गाढ़ा दूध होता है, जिसमें साधारण दूध की अपेक्षा विटामिन्स, खनिज तथा प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है। इसमें रोग निरोधक पदार्थ जिन्हें एन्टीबाडीज कहते हैं भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एंटीबाडीज नवजात बच्चे को रोग ग्रस्त होने से बचाती है। खीस में दस्तावर गुण भी होते हैं, जिससे नवजात बच्चे की आंतों में जन्म से पहले का जमा मल (म्युकोनियम) बाहर निकल जाता है तथा उसका पेट साफ हो जाता है। खीस को बच्चे के पैदा होने के 4-5 दिन तक नियमित अंतराल पर अपने शरीर के बजन के दसवें भाग के बराबर पिलाना चाहिए। अधिक मात्र में खीस पिलाने से बच्चे को दस्त लग सकते हैं।

- यदि किसी कारणवश (जैसे माँ की अकस्मात् मृत्यु अथवा माँ का अचानक बीमार पड़ जाना आदि) खीस उपलब्ध न हो तो किसी और पशु की खीस को प्रयोग किया जा सकता है। यदि खीस किसी और पशु का भी यह उपलब्ध न हो तो नवजात बच्चे को निम्नलिखित मिश्रण दिन में 3-4 बार दिया जा सकता है। 300 मि.ली. पानी को उबाल कर ठंडा करके उसमें एक अंडा फेंट लें। इसमें 600 मि.ली.साधारण दूध व आधा चमच अंडी का तेल मिलाएं। फिर इस मिश्रण में एक चम्मच फिश लिवर ओयल तथा 80 मि.ग्रा.औरियोमायसीन पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को देने से बच्चे को कुछ लाभ हो सकता है। प्राकृतिक खीस में पाई जाने वाली एंटीबाडीज नवजात बच्चे को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। खीस पीने के दो घंटे के अन्दर बच्चा म्युकोनियम (पहला मल) निकाल देता है, लेकिन ऐसा न होने पर बच्चे को एक चम्मच सोडियम बाईकार्बोनेट को एक लीटर गुनगुने पानी में घोल कर एनीमा दिया जा सकता है।
- कई बार नवजात बच्चे में जन्म से ही मल द्वार नहीं होता इसे एंट्रेसिया एनाई कहते हैं। यह एक जन्मजात बिमारी है तथा इसके कारण बच्चा मल विसर्जन नहीं कर सकता और वह बाद में मृत्यु का शिकार हो जाता हैं। छोटी सी शल्य क्रिया द्वारा ठीक मल द्वार के स्थान पर एक +के आकार का चीर दिया जाता है तथा शल्य क्रिया द्वारा मल द्वार को मलाशय (रेक्टम) से जोड़ दिया जाता है, जिससे बच्चा मल विसर्जन करने लगता है। यह कार्य पशुपालक को स्वयं न करके नजदीकी पशु चिकित्सालय में करना चाहिए क्योंकि कई बार इसमें जटिलतायें पैदा हो जाती है।
- कभी-कभी बच्छियों में जन्म से ही चार थनों के अलावा अतिरिक्त संख्या में थन पाए जाते है। अतिरिक्त थनों को जन्म के कुछ दिन बाद जीवाणु रहित की हुई कैंची से काट कर निकाल देना चाहिए। इस क्रिया में सामान्यतः खून नहीं निकलता। अतिरिक्त थनों को न काटने से बच्छी के गाय बनने पर उससे दूध निकालते समय कठिनाई होती है।
- यदि पशु पालक बच्चे को माँ से अलग रखकर पालने की पद्धति को अपनाना चाहता है तो उसे बच्चे को शुरू से ही बर्तन में दूध पीना सिखाना चाहिए तथा उसे मन से जन्म से ही अलग कर देना चाहिए। इस पद्धति में बहुत सफाई तथा सावधानियों की आवश्यकता होती है, जिनके बिना बच्चों में अनेक बिमारियों के होने की सम्भावना बढ़ जाती है।
- नवजात बच्चों को बड़े पशुओं से अलग एक बाड़े में रखना चाहिए, ताकि उन्हें चोट लगने का खतरा न रहे। इसके अतिरिक्त उनका सर्दी व गर्मी से भी पूरा बचाव रखना जरूरी है।
- **नाल पर टिंचर आयोडिन लगाना:** जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की नाल साफ ब्लेड से नाभि से एक इंच उपर काटें। नाल पर टिंचर आयोडिन नामक दवाई का फोहा रखना खहिए। पैदा होते ही नवजात शिशु को साफ कपड़े से पोंछे जन्मनाल को एक इंच दूरी से काट कर टिंचर बेंजोइनलगा दें।
- **ठंड से बचाव:** कुछ बछड़े-बछिया बहुत अधिक ठंड की वजह से निमोनिया से भी मरते हैं। पशुपालकों को चाहिए कि जाड़े के दिनों में बछड़े-बछिया को ठंड से बचाएं।
- **कृमिनाशक दवाई पिलाना:** आमतौर पर भैंसों के तो 55 प्रतिशत बच्चों की जन्म के एक माह मे मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण है। उनके पेट में गोल कृमि का संक्रमण होना। यदि गाय-भैंसों के नवजात बछड़ों को एक माह की आयु में ही पिपरेजीन नामक औषधि के दो ढक्कन पिला दें तो उन्हें रोग से बचाया जा सकता है।

आज के नवजात पशुवत्स कल के वयस्क पशु होते है , यदि इनपर समय रहते ध्यान दे दिया जाए तो श्वेत क्रांति के स्वप्न को दहलीज तक लाना सुगम हो जाता है।

खाद्य फसलों के साथ फूलों की खेती से बढ़ेगा परागण, पैदावार और गुणवत्ता दोनों में होगा सुधार

एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के पारिस्थितिकीविदों द्वारा दक्षिण भारत में किए एक अध्ययन से पता चला है कि खाद्य फसलों के साथ की गई फूलों की खेती से न केवल परागण करने वाले जीवों को फायदा होगा, साथ ही इससे फसलों की पैदावार और गुणवत्ता में भी सुधार आ सकता है। भारत में किए अपनी तरह के इस पहले अध्ययन के नतीजे जर्नल ऑफ एप्लाइड इकोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं। अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मोरिंगा यानी सहजन (ड्रमस्टिक) की फसल पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसे सुपरफ्रूड के रूप में भी जाना जाता है। भारत में इसकी खेती आमतौर पर छोटे किसानों द्वारा की जाती है।

आमतौर पर सहजन का उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है। लेकिन वास्तव में यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण इसे खास बनाते हैं। वहीं पारिस्थितिकी तंत्र के नजरिए से देखें तो परागण बेहद महत्वपूर्ण है जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी अहम रूप से योगदान देती है। इन परागणकों की भूमिका इसी से समझी जा सकती है कि यह कीट 80 फीसदी से ज्यादा पौधों को परागित करते हैं जो इंसानों समेत अनगिनत जीवों के भोजन का प्रमुख स्रोत हैं।

बगीचों में मोरिंगा के पेड़ों के साथ-साथ गेंदे के फूल और लाल चने की फसल लगाने से शोधकर्ताओं को फूलों पर आने वाले कीटों की बहुतायत और विविधता बढ़ाने में मदद मिली, जिसके परिणामस्वरूप परागण में सुधार हुआ, फसल की पैदावार में भी वृद्धि देखी गई। शोधकर्ताओं का कहना है कि, कृषि भूमि पर जंगली फूलों को लगाना एक जांची-परखी विधि है। यह तकनीक परागणकों की संख्या बढ़ाने के लिए जानी जाती है। उनका आगे कहना है कि, दक्षिण भारत में किसानों के सहयोग से की गई इस रिसर्च का मकसद मोरिंगा के बगीचों में देशी मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी सह-फूल वाली फसलों को डिजाइन करना था। शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के कन्नीवाड़ी क्षेत्र में मोरिंगा के 24 बागों में छोटे किसानों के साथ मिलकर काम किया। जहां 12 बगीचों में उन्होंने लाल चना और गेंदा के फूल लगाए, जबकि अन्य 12 बगीचों में कोई सह-फूल वाली फसल नहीं लगाई गई थी। इन बगीचों की तुलना करने पर पता चला जिन बगीचों में लाल चने और गेंदें के फूल लगाए गए थे वहां परागणकों की संख्या 50 फीसदी और उनकी विविधता 33 फीसदी अधिक थी।

-कृषि उपज के ऑनलाइन कारोबार को मिल रहा बढ़ावा

किसानों का साथी बना ई-नाम, 27 सूबों में नेटवर्क

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार के ऑनलाइन मंडी प्लेटफार्म ई-नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार से अब 1361 मंडियां जुड़ चुकी हैं। देश की 2000 मंडियों को अगले कुछ ही वर्ष में इससे जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। हालांकि जब 14 अप्रैल, 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी तब इसमें सिर्फ 21 मंडियां ही शामिल हुई थीं। यह कृषि क्षेत्र के लोगों का ऑनलाइन ट्रेडिंग में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। इस प्लेटफार्म से करीब 1.77 करोड़ किसान जुड़ चुके हैं। दरअसल, इस प्लेटफार्म के आने के बाद किसान और खरीदार के बीच का सीधा संबंध और गहरा हुआ है। दलालों की भूमिका काफी हद तक खत्म हो गई है। हालांकि, कुछ सरकारी एजेंसियां अब भी ऑफलाइन कारोबार को प्रमोट करने में जुटी हुई हैं, जबकि ऐसा करने से देश को नुकसान पहुंच रहा है। इस प्लेटफार्म का 27 सूबों में विस्तार हो चुका है। इससे किसानों को अपनी कृषि उपज का कारोबार करने में बड़ी मदद मिल रही है। वो एक बड़े दायरे में उपज बेच पा रहे हैं। इस प्लेटफार्म पर 193 कमोडिटी की ट्रेडिंग हो रही है। ई-नाम एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है। जो पूरे भारत में मौजूद एग्री प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क में जोड़ने का काम करता है। इसका मकसद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध करवाना है। इस नेटवर्क से 3,366 एफपीओ का जुड़ना किसी बड़े दांव से कम नहीं है। इसके जरिए किसान मंडियों में भौतिक रूप से परिवहन किए बिना ही प्लेटफॉर्म पर अपनी उपज बेच रहे हैं।

कारोबार में भारी उछाल

ई-नाम से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस प्लेटफार्म पर किसानों के बढ़ते भरोसे की वजह से कारोबार में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। साल 2022-23 में अप्रैल से नवंबर के बीच अंतर मंडी व्यापार सिर्फ 343.75 करोड़ रुपये का था जो 2023-24 में इसी अवधि के दौरान बढ़कर 988.54 करोड़ रुपए हो गया है। यानी इसमें 188 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है। अगर मात्रा में बात करें तो 120 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है। साल 2022-23 के अप्रैल से नवंबर के बीच 132713 मीट्रिक टन उपज का कारोबार हुआ था जो 2023-24 की इसी अवधि के दौरान बढ़कर 291447 मीट्रिक टन हो गया है।

कैसे होता है ट्रेड

फार्मगेट मॉड्यूल का उपयोग करके कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा सहित 11 राज्यों के किसानों ने मक्का, कपास, धान, कच्चा केला और सब्जियों जैसी कई वस्तुएं बेची हैं। दरअसल, यह मॉड्यूल कृषि घाटे के साथ-साथ परिवहन और हैंडलिंग खर्च को कम करता है। किसान ई-एनएएम प्लेटफॉर्म पर अपने निकटतम एपीएमसी मंडियों के माध्यम से खेत से वस्तुओं के लॉट साइज की तस्वीरें अपलोड करते हैं। मंडियों में रजिस्टर्ड खरीदार कृषि उपज के लिए बोली लगाते हैं और किसानों के बैंक खाते में भुगतान करने के बाद फार्मगेट से वस्तुओं को उठा लेते हैं।

ई-नाम पर पराली का ट्रेड

उर्जा मंत्रालय के एक अनुरोध पर हाल ही में धान की पराली से प्राप्त बायोमास का ट्रेड ई-नाम की सूची में डाला गया है। अंबाला मंडी में ई-एनएएम का उपयोग करके कच्चे बायोमास (कृषि-अवशेष) का व्यापार का परीक्षण किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत काम करने वाला लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) ई-नाम को संचालित कर रहा है। देश भर में करीब 2,700 कृषि उपज मंडियां और 4,000 उप-बाजार हैं। पहले कृषि उपज मंडी समितियों के भीतर या एक ही राज्य की दो मंडियो में कारोबार होता था। लेकिन ई-नाम से राज्यों की सीमाओं का प्रतिबंध खत्म कर दिया है।

ऑनलाइन ट्रेड की जरूरत

कृषि विशेषज्ञ बिनोद आनंद का कहना है कि ई-नाम प्लेटफार्म का और विस्तार होना चाहिए। एफसीआई और नेफेड कृषि उपज की जितनी ऑफलाइन ट्रेनिंग करते हैं उसे बंद करके उसका ई-नाम पर ट्रेड शुरू करने की जरूरत है। ऑनलाइन ट्रेडिंग को बढ़ावा देने से किसानों को अच्छा दाम मिलेगा और उपभोक्ताओं को फायदा होगा। क्योंकि किसान के कंज्यूमर के बीच की कई कड़ियों का काम खत्म हो जाएगा। कारोबार में जितने कम भागीदार होंगे किसानों और उपभोक्ताओं को उतना ही फायदा होगा। ऑनलाइन ट्रेड बढ़ने से देश में ईंधन की काफी बचत होगी।

केन्द्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट

कोरोना के बाद से थाली में बढ़ गए 15 अंडे
पोल्ट्री में अंडे और चिकन का प्रोडक्शन बढ़ा

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

कोरोना के बाद से हैल्थ को लेकर लोग खासे जागरुक हो गए हैं। ख ासतौर पर इम्यूनिटी को लेकर खानपान में बदलाव भी आया है। प्रोटीन डाइट पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। शायद यही वजह है कि कोरोना जैसी जानलेवा महामारी के बाद से हर एक भारतीय की थाली में औसत सालाना 15 अंडे (पोल्ट्री ऐग) बढ़ गए हैं। ये आंकड़ा केन्द्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने जारी किया है। एक्सपर्ट का मानना है कि सस्ता, प्योर और कम डाइट में ज्यादा प्रोटीन की वजह से अंडों की डिमांड बढ़ी है। अंडों की डिमांड बढ़ने से जहां पोल्ट्री सेक्टर में खुशी है, वहीं उनकी नजर सालाना 180 अंडों पर है। क्योंकि वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइड लाइन के मुताबिक प्रति व्यक्ति को सालभर में कम से कम 180 अंडे खाने चाहिए। डॉक्टर और डायटिशियन का कहना है कि जरूरी प्रोटीन के लिए अंडे की खपत का ये आंकड़ा अभी बहुत कम है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक अंडा भी रोजाना नहीं खा रहे हैं। खासतौर से बढ़ती उम्र के बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए तो अंडा बहुत ही ज्यादा जरूरी है।

अंडों का प्रोडक्शन और खपत

देश में अंडों की डिमांड और प्रोडक्शन दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते तीन साल में ही अंडों का प्रोडक्शन 24 बिलियन बढ़ा है। डिमांड में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सस्ता होने और क्वलिटी में बेहतर होने के चलते एक्सपोर्ट की डिमांड भी बढ़ने लगी है। मंत्रालय के आंकड़ों की मानें तो साल 2019-20 में 114.38 बिलियन अंडों का प्रोडक्शन हुआ था। वहीं 2020-21 में 122 बिलियन, 2021-22 में 129.60 बिलियन और 2022-23 में 138.38 बिलियन अंडों का प्रोडक्शन हुआ है।

प्रति व्यक्ति के हिस्से में आने वाले अंडों की संख्या	
2000-01	36
2004-05	42
2007-08	47
2010-11	53
2013-14	60
2015-16	65
2017-18	73
2018-19	79
2019-20	86
2020-21	90
2021-22	95
2022-23	101

10 साल में आपकी थाली में बढ़े 41 अंडे

पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के कोषाध्यक्ष रिकी थापर ने किसान तक को बताया कि अगर 10-12 साल पहले की बात करें तो हर साल अंडे का प्रोडक्शन बढ़ने का रेट दो से तीन अंडे थे। लेकिन 2016-17 के बाद से अंडे के प्रोडक्शन ने लम्बी छलांग लगानी शुरू कर दी। अगर 10 साल पहले की बात करें तो औसत प्रति वयक्ति के हिस्से में सालाना 60 अंडे आते थे। लेकिन 2022-23 में ये आंकड़ा 101 अंडों पर पहुंच गया है। हालांकि हम इस आंकड़े को 180 अंडों पर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि खासतौर पर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार के लिए प्रोटीन का ये सबसे सस्ता साधन है। इतना ही नहीं कम पैसों में और आसान डाइट में अंडे से ज्यादा प्रोटीन किसी और चीज में नहीं मिल सकता है। चलते-फिरते, मेट्रो ट्रेन में या बस में बैठकर आराम से खाए जाने वाला अंडा ही है। मेट्रो सिटी की तेज रफ्तार जिंदगी में सबसे आसानी से मिलने और बनने वाला नाश्ता भी अंडा ही है।

पीएम किसान लाभार्थियों को 6 हजार की जगह अब 12 हजार रुपए मिलेंगे

भोपाल। केंद्र सरकार किसानों को कृषि कार्यों में आर्थिक मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में सालाना 6,000 रुपए देती है। यह रकम 3 किस्तों में लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। योजना के लाभार्थी किसानों को अब 6 हजार रुपये की जगह 12 हजार रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। क्योंकि, राजस्थान में चुनावी सभा में पीएम मोदी ने किसानों को दोगुनी रकम देने का वादा किया था। पीएम मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से देशभर के 8.11 करोड़ किसानों के लिए 15वीं किस्त के रूप में कुल 18.61 हजार करोड़ रुपए जारी किए थे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 15 किस्तों में 11 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को केंद्र सरकार 2.80 लाख करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर चुकी है।

दोगुनी होगी सम्मान राशि

राजस्थान में विधानसभा चुनावों के तहत 20 नवंबर को हनुमानगढ़ में चुनावी रैली को पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की रकम दोगुनी करने की बात कही थी। पीएम ने अपने भाषण में कहा था कि राजस्थान बीजेपी ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए 12,000 रुपए देने का फैसला किया है।

हमें ऐसे पौधे लगाने चाहिए जिन पर मधुमक्खियां आकर परपरागण कर सकें: डॉ. अरविंद कुमार शुक्ला

किसान मधुमक्खी पालन की बारिकियां व खूबियां समझकर एक नये व्यवसायी व सफल उद्यमी बनें: डॉ. एस. आरके सिंह

मधुमक्खी पालन बदल सकता है किसान का जीवन, जरूरत है तो सोच बदलने की

ग्वालियर। जागत गांव हमार

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एवं कृषि विज्ञान केन्द्र ग्वालियर द्वारा मधुमक्खी पालन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कायज़्शाला एवं जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिसका लक्ष्य मधुमक्खी पालन कृषि आधारित व्यवसाय को बढ़ावा देना है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में मधुमक्खी पालन में कर्नाटक के प्रगतिशील मधुमक्खी पालक डॉ. मधुकेश्वर हेगड़े ने अपने उद्बोधन में बताया कि वह किस प्रकार एक गरीब परिवार से उठकर एक प्रगतिशील उद्यमी बने। जीवन में उन्हें कितनी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। हेगड़े ने कहा मेरे जीवन की सफलता में मेरी माता व उनके दिये संस्कारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप सभी भी अपने माता-पिता व धरती मां का सम्मान करें। उनके द्वारा शहद से बने उत्पाद हनी जैम, लेमन जिंजर हनी जूस, रॉयल जैली, तुलसी हनी, सुपारी हनी, जामुन हनी, हनी लिप बाम, हनी बीटरूट लिप बाम, हनी पॉलन, हनी सॉप आदि उत्पादों का प्रदशज़्न कर किसानों को संबोधित किया। हेगड़े द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए 500 से ज्यादा कॉलोनियां बनाई गयी है, जिनसे उनकी स्वयं की वर्षभर की आय 2 करोड़ 28 लाख रुपए है। साथ ही वे 300 कर्मचारियों को रोजगार भी दे रहे है। हाल ही में भारत सरकार की परिवहन मंत्री

नितिन गडकरी द्वारा नेशनल मिलिनियर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जबलपुर अटारी जोन 9 के निदेशक डॉ. एसआरके सिंह ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला से आप सभी युवा एवं किसान मधुमक्खी पालन की बारिकियां व खूबियां समझकर एक नये व्यवसायी व सफल उद्यमी बने। साथ ही उत्कृष्ट व विकसित भारत के सपने में अपनी सहभागिता करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरविन्द कुमार शुक्ला ने कहा कि सफल उद्यमी मधुकेश्वर हेगड़े की सफलता से मुझे प्रेरणा मिली है, आप सब भी इनसे प्रेरणा लें। उन्होंने कहा कि हमने अपना जीवन केवल धान व गेहूं की फसल पर ही निर्भर कर लिया है। हमें विविधीकरण कर ऐसे पौधे लगाने चाहिए जिन पर मधुमक्खियां आकर परपरागण कर सके। हमें और आपको प्रकृतिपरक होने की आवश्यकता है। हम अपनी फसल तकनीक को बदलें ताकि सरसों की फसल के मौसम के अतिरिक्त भी अन्य मौसम में मधुमक्खी पालन किया जा सके। डॉ. शुक्ला ने कहा सफल होने के लिए शिक्षा ही एक माध्यम नहीं है यदि सफल होने चाहते है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे है। आपकी सफलता में व्यवहार, शैली, आत्मविश्वास आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सबसे उपयुक्त फसल सरसों

कार्यक्रम में निदेशक विस्तार सेवायें डॉ. वायपी सिंह, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के रंजीत सिंह, अटारी जोन 9 के वैज्ञानिक डॉ. हरीश मंचासीन रहे। कार्यशाला में कुलसचिव अनिल सक्सेना, कृषि विज्ञान केन्द्र ग्वालियर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राज सिंह कुशवाह, लगभग 200 किसान प्रत्यक्ष रूप से व अन्य 1000 किसान ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। कार्यशाला का स्वागत भाषण कृषि वैज्ञानिक अरविन्द कौर, धन्यवाद भाषण कृषि वैज्ञानिक डॉ. अमिता शर्मा व संचालन वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रश्मि वाजपेयी द्वारा किया गया। तकनीकी सत्रों में बताया गया कि मधुमक्खियों द्वारा फसलों में परपरागण क्रिया होती है जिससे फसलों के बीज उत्पादन तथा फलदार वृक्षों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त फसलों जैसे सरसों, तोरिया, बरसीम, अजवायन, धनिया, बाजरा, तिल, नीम, व अन्य फूलों वाले पेड-पौधे मधुमक्खियों के लिए मधुरस व पराग का उत्तम स्त्रोत है।

जबलपुर में मटर का सही दाम नहीं मिलने से गुस्साएं किसानों ने हाईवे पर किया चक्काजाम

जबलपुर। जबलपुर में मटर का सही दाम न मिलने से गुस्साएं किसानों ने हाईवे पर किया चक्काजाम कर दिया। जबलपुर और उसके आस-पास का क्षेत्र मटर उत्पादन के लिए जाना जाता हैं। इस बार प्रदेश में मटर का उत्पादन भी बंपर हुआ है। लेकिन इतने उत्पादन के बाद भी किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा हैं।

जबलपुर उपज मंडी में खपत से ज्यादा मटर पहुंच रही हैं। जिससे मटर के दाम भी कम हो गए हैं। जिसके बाद किसानों और मंडी के थोक व्यापारियों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। इसके चलते मटर के दाम कम किए जाने पर नाराज किसानों ने सोमवार को जमकर हंगामा किया। इस दौरान किसानों ने कृषि उपज मंडी के मुख्य गेट पर अपनी गाड़ियों को खड़ा करके सड़क को जाम कर दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन किसानों का कहना है कि उनको मटर की बहुत ही कम कीमत

मिल रही हैं, जिस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। वैसे इस समय किसानों को मटर की कीमत कम से कम 20 से 30 रुपए किलो मिलनी चाहिए थी लेकिन इसका दाम किसानों का 10 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा है।

पुलिस ने शांत कराया और यातायात बहाल किया गया

किसानों का मटर के दाम को लेकर धरना प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि किसान सड़कों पर उतर आए। इसके चलते किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर चक्काजाम कर दिया। वहीं प्रशासन को मामले की खबर लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची ने किसानों को समझाया। इसके बाद पुलिस ने हंगामे को शांत कराया और यातायात बहाल किया गया।

लागत से भी कम दाम में बिक रहा मटर

जबलपुर मंडी में मटर 4 से 5 रुपए किलो बिक रहा है। जबकि किसानों का कहना है कि मटर की तुड़ाई में ही चार से पांच रुपए लग जाते हैं। इसके बाद मंडी टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मिलाकर घर पर ही मटर का दाम 8 से 10 रुपए पड़ता हैं। जिस पर व्यापारी मटर की 5 रुपये से अधिक कीमत देने को तैयार नहीं हैं। इस मामले में किसानों ने सरकार से मदद की अपील की है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कराएं रबी फसलों का बीमा

नई दिल्ली। सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे किसानों को लाभ मिल रहा है। इन्हीं में से एक योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। इस योजना के जरिए किसानों को खड़ी फसलों के नुकसान के खिलाफ बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के तहत रबी फसलों के लिए बीमा कवर का प्रीमियम 1.5प्रतिशत है। वहीं, सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है। जिसका अर्थ ये है कि किसानों को केवल 0.75प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होता है। फिलहाल फसल बीमा सप्ताह चल रहा है। किसान भाई कवर लेने के लिए जल्द फसलों का बीमा करा लें।

ये नुकसान होते हैं कवर

प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट, बीमारियां कवर होती हैं।

बीमा से मिलेगा ये लाभ

इसके तहत किसानों को खड़ी फसलों के नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही ये किसानों को अपनी आय को बनाए रखने और खेती जारी रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। फसल बीमा का एप्लीकेशन फार्म, फसल बुआई का प्रमाण-पत्र, खेत का नक्शा, खेत का खसरा या बी-1 की प्रति, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण या पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है।

विश्व मृदा दिवस पर केवीके पन्ना में कृषक संगोष्ठी, किसान और जमीन के लिए फायदेमंद पशु: एपी सुमन

डॉ. पीएन त्रिपाठी बोले-रसायनिक खाद के असंतुलित प्रयोग हानिकारक

मिट्टी की सेहत सुधारने किसानों को गोबर गौमूत्र आधारित प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना होगा

पन्ना। जागत गांव हमार

विश्व मृदा दिवस के अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र पन्ना एवं समर्थन संस्था द्वारा संयुक्त रूप से डब्लूएचएच के सहयोग से कृषक संगोष्ठी का आयोजन कृषि महाविद्यालय परिसर लक्ष्मीपुर में किया गया। कार्यक्रम में जिले के उप संचालक एपी सुमन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बताया कि मिट्टी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। किसानों द्वारा असंतुलित रूप से रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे मिट्टी कठोर हो रही है एवं उसकी उर्वरकता खत्म हो रही है। मिट्टी की भौतिक दशा को सुधारने के लिए कृषकों को गोबर गौमूत्र आधारित प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता महोदय डॉ. व्हीके यादव ने कृषकों को मिट्टी परीक्षण आधारित संतुलित उर्वरक उपयोग तथा खरपतवारनाशी एवं अन्य रसायनों का कम से कम उपयोग करने की सलाह दिया। केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. पीएन त्रिपाठी ने बताया कि रसायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग से मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। अधिक फसल उत्पादन लेने के उद्देश्य से मिट्टी से पोषक तत्वों का निरंतर निष्कासन हो रहा है, परंतु उसकी पूर्ति के लिए कृषकों द्वारा एकीकृत पोषक तत्व प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

17 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता

फसलों को 17 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, परंतु कृषकों द्वारा केवल यूरिया एवं डीएपी के माध्यम से दो ही मुख्य तत्वों नत्रजन एवं स्फुर की पूर्ति हो पाती है। शेष पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी होती जा रही है। फसल चक्र में दलहनी फसलों एवं हरी खाद की फसलों जैसे सनई, ढैंचा का प्रयोग करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। लक्ष्मीपुर पंचायत की सरपंच नीलम खंगार द्वारा उपस्थित कृषकों को बताया गया कि हम सभी को मिलकर मिट्टी एवं जल संरक्षण की ओर कार्य करना होगा। इस संबंध में सभी पंचायतों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। पशु चिकित्सक निगम द्वारा कृषकों को पशुओं की विभिन्न बीमारियों एवं उनके निदान के बारे में बताया गया। कृषि फसल बीमा के पंकज कुशवाह द्वारा कृषकों को रबी फसलों के बीमा कराये जाने पर विस्तृत चर्चा किया।

मिट्टी का गिरता स्वास्थ्य चिंतनीय विषय

समर्थन संस्था के ज्ञानेन्द्र तिवारी द्वारा बताया गया कि मिट्टी का गिरता स्वास्थ्य चिंतनीय विषय है मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए प्राकृतिक खेती, केंचुआ खाद एवं मोटा अनाज की खेती को फसल चक्र में अपनाना होगा उनके द्वारा जल ही जीवन है, जय जवान जय किसान एवं स्वास्थ्य धरा खेत हरा का उद्घोष कराया गया। प्रगतिशील कृषक कीर्तन देवी पटेल ने कहा कि हम सभी महिलायें प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं और महिलाओं को प्राकृतिक खेती के सिखाने का काम भी कर रहे हैं। कार्यक्रम में डॉ. आरके जायसवाल, डॉ. आरपी सिंह, रितेश बागोरा, आशीष विश्वास, चालीसजा, ज्योति कुशाहा, लखनलाल शर्मा एवं जलमित्र सहित कुल 350 प्रगतिशील कृषकों ने हिस्सा लिया।

केंद्रीय विद्यालय के छात्रों को दी जैविक कृषि की जानकारी

छतरपुर। गत दिवस कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय छतरपुर के प्राचार्य मनीष रूसिया के निर्देशन में आरके जैन एवं मुकुल नंदा द्वारा 90 छात्र एवं छात्राओं का भ्रमण कराया गया, जिसमें केंद्र की प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. वीणापाणी श्रीवास्तव द्वारा छात्रों को कृषि विज्ञान केंद्र के उद्देश्यों तथा कार्य के बारे में विस्तार से बताया गया। डॉ. कमलेश अहिरवार (वैज्ञानिक उद्यानिकी) के द्वारा फल, फूलों एवं सब्जियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, विस्तार से बताया और जैविक खेती के महत्व के बारे में भी विस्तार से बताया गया साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र में प्रदर्शित नर्सरी इकाई, उद्यानिकी फसल संग्रहालय इकाई, औषधि इकाई तथा फलोउद्यान पपीता प्रदर्शन इत्यादि इकाईयों का भ्रमण कराया और प्रदर्शित इकाईयों के बारे में विस्तार से समझाया भी गया। आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय से अतिक्षा, रश्मि भारती, रवि एवं बद्री प्रसाद भी उपस्थित रहे।

बैतूल जिले में प्लांट क्लीनिक आयोजित किए गए

बैतूल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा गत दिनों जिले के ग्राम जम्बाड़ा, भड़ूस, चोपना, करपा, बोरीखुर्द, चौथिया एवं हीरापुर में प्लांट क्लीनिक आयोजित किए गए। प्लांट क्लीनिक दलों के द्वारा किसानों को खरीफ बुआई, बीजों का चयन, बीजोपचार, कल्चर का उपयोग, बीजों की उन्नत किस्में, उर्वरकों का संतुलित उपयोग, जैविक खाद का महत्व, फसल विविधीकरण की उपयोगिता, कीट एवं रोगों के लक्षण व निदान सहित मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर संतुलित उवरकों का उपयोग करने की सलाह दी गई। इसके अलावा किसानों को एमपी किसान एप पर रजिस्ट्रेशन करवाने, पशुओं के रखरखाव एवं रोग नियंत्रण सहित उद्यानिकी व मत्स्य विभाग की योजनाओं की जानकारी और समसामयिक की सलाह भी दी गई। इस दौरान प्लांट क्लीनिक दलों में कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी, उद्यानिकी अधिकारी, मत्स्य विभाग के अधिकारी एवं पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को आवश्यक सलाह दी गई ।

कृषि वैज्ञानिकों ने बताया बदलते मौसम में किसान कैसे करें फसलों की देखभाल

बैतूल। कृषि विज्ञान केंद्र, बैतूल के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. व्हीके वर्मा के अनुसार वर्तमान मौसम जिसमें लगातार बादल बने हुए हैं एवं तापमान सामान्य से अधिक है, जिसके कारण रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मसूर आदि में वांछित बढ़वार की कमी देखी गई है एवं कीट-व्याधि का प्रकोप आरंभिक अवस्था में देखा गया है। केन्द्र के पौध संरक्षण वैज्ञानिक आरडी बारपेटे ने बताया कि गेहूं की फसल में संभवत: पहली बार इस अवस्था में खरीफ मौसम के प्रमुख कीट फॉल आर्मी वर्म, चने की इल्ली, तम्बाकू की इल्ली आदि का प्रकोप देखा गया है। इन कीटों के साथ-साथ गेहूं एवं चना दोनों फसलों में जड़ एवं तना में फफूंदजन्य बीमारियों का संक्रमण भी परिलक्षित हो रहा है। आगामी दिनों में यदि मौसम साफ होकर तापमान में कमी नहीं हुई तो इन कीट-व्याधियों का प्रकोप फसलों को ज्यादा नुकसान करेगा।

- वर्तमान मौसम एवं फसल की अवस्था को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रबंधन उपाय करने की आवश्यकता है-
- रबी फसलों को पानी की पर्याप्त उपलब्धता होने पर भी क्रांतिक सिंचाई ही करें, अतिरिक्त नमी इन फसलों में कीट एवं व्याधि को बढ़ाते हैं।
- गेहूं की फसल में पीलापन या कीट-व्याधि का प्रकोप होने पर यूरिया के प्रयोग को स्थगित रखें, नत्रजन की पूर्ति हेतु नैनो यूरिया को प्राथमिकता दे। यह फसल, भूमि- पर्यावरण के प्रति मित्रवत है, साथ ही इसकी कीमत भी कम है।
- गेहूं की फसल में फाल आर्मी वर्म (कीट की प्रमुख पहचान इल्ली के सिर पर उल्टे व्हाय आकर की रेखाएं) के प्रकोप होने पर इमेमेक्टिन बेंजोएट 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी या बिवेरिया बेसियाना 2.5 मिली का छिड़काव करें।
- गेहूं में खरपतवार प्रबंधन के लिए रासायनिक खर पतवारनाशियों का प्रयोग 25 दिन की फसल होने पर ही करें।
- कीटनाशक एवं किसी भी तरह के पोषक तत्वों का मिश्रण उपयोग न करें।
- चने की फसल में संभव होने पर डौरे चलाएं।

भोपाल में मिट्टी और पानी- जीवन का एक स्रोत विषय पर कृषि शिक्षा दिवस का आयोजन

भोपाल। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान , भोपाल ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के भोपाल चैप्टर के सहयोग से सोमवार को मिट्टी और पानी- जीवन का एक स्रोत विषय के तहत कृषि शिक्षा दिवस मनाया। डॉ. एसपी दत्ता, निदेशक, भाकृ अनुप-आई आई एसएस, भोपाल तथा एनएएएस के फेलो ने कृषि उत्पादन और मानव स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए मिट्टी के महत्व पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने स्कूली बच्चों से भी बातचीत की। छात्रों के लिए मृदा स्वास्थ्य जागरूकता पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में सरकारी उच्च-माध्यमिक विद्यालयों, यथा- एच.एस.एस. सरदार पटेल , होली क्रॉस को-एड स्कूल तथा ब्रिगेडियर त्रिवेदी मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भोपाल के बच्चों ने भाग लिया।

कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा विश्व मृदा दिवस मनाया गया

तकनीकी का प्रयोग करें, मृदा को बनाए रखें जीवित

रीवा। रीवा कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा द्वारा विश्व मृदा दिवस का आयोजन अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रीवा डॉ. एसके त्रिपाठी की उपस्थिति वं कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एके पांडेय के मार्गदर्शन मे किया गया। वर्ष 2024 की थीम मृदा एवं जल: जीवन का स्त्रोत रही। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ. एसके त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में उन्होने छात्रों एवं कृषकों से आग्रह किया कि वे भारत सरकार की मंशानुरूप अपने मृदा के स्वास्थ व उर्वरता में सुधार लाने के लिए हर सम्भव संसाधन संरक्षण तकनीकी का प्रयोग करे व मृदा को जीवित बनाए रखें। ताकि जनसंख्या की आहार संबंधी अवश्यक्ताओं की पूर्ति हो सके। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एके पांडेय ने हरी खाद के साथ-साथ खेत के अवशेषों के प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया। जिससे मृदा मे कार्बनिक पदार्थों के स्तर और मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सके।

कार्यक्रम प्रभारी एके पटेल ने इस अवसर पर जानकारी देते हुए बताया कि हमारे भोजन का 95 प्रतिशत मिट्टी से उत्पन्न होता है। फसलों/पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों मे से 15 मृदा से ही प्राप्त होते हैं। 2050 में विश्व की आहार संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वर्तमान उत्पादन से 60 प्रतिशत अधिक उत्पादन की आवश्यकता होगी। कुल मृदा का 33 प्रतिशत हिस्सा खराब अनुत्पादक होने की करार पर है। केवल मृदा के उचित प्रबंधन के द्वारा ही लगभग 58 प्रतिशत भोजन की आपूर्ति संभव हो सकती है। इस अवसर पर डा आरपी जोशी डॉ. राजेश सिंह, डॉ. किंजुलक सिंह, डॉ. सीजे सिंह, डॉ. बीके तिवारी डा अखिलेश कुमार, डॉ. स्मिता सिंह डॉ. केएस बघेल एमके मिश्रा, मंजू शुक्ला ने भाग लिया।

-देशभर में 45 दिन तक छूटे किसानों के रजिस्ट्रेशन होंगे

पीएम किसान योजना के लिए सरकार ने छेड़ा अभियान

भोपाल। जागत गांव हमार

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पात्र किसानों को देने के लिए केंद्र सरकार ने देशव्यापी सैचुरेशन कैंपेन शुरू कर दिया है। इस कैंपेन के जरिए योजना का लाभ पाने से छूटे गए लोगों के रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। यह कैंपेन 1 दिसंबर से शुरू हो गया है और 45 दिनों तक चलेगा ताकि वित्तीय मदद देने वाली इस केंद्रीय योजना का लाभ किसानों तक पहुंच सके। वर्तमान में योजना के तहत सालाना 6000 रुपए लाभार्थियों को दिए जाते हैं जो जल्द ही 12000 रुपए होने की संभावना है। पीएम किसान योजना को 24 फरवरी 2019 को किसानों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। पीएम किसान योजना से किसानों को आर्थिक रूप से स्थिरता मिलती है और वे अपनी खेती और कृषि सक्रियता को बेहतर बनाने में सक्षम होते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है।

छूटे किसानों को जोड़ने चलाया कैंपेन

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार पीएम किसान योजना का लाभ देने के लिए सैचुरेशन कैंपेन शुरू हो गया है। 45 दिवसीय ग्राम स्तरीय सैचुरेशन कैंपेन 15 जनवरी 2024 तक चलेगा। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। कैंपेन के जरिए देश का हर पात्र किसान इस मुहिम से जुड़ सकता है और पीएम किसान योजना का लाभ ले सकता है।

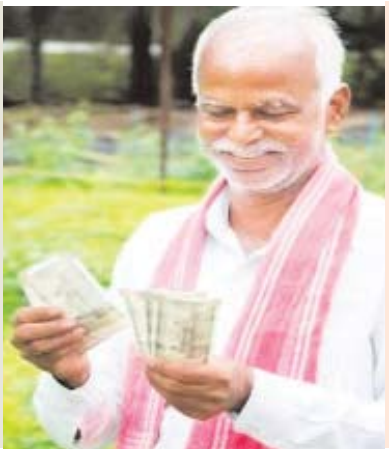

किसानों को 2.80 लाख करोड़ मिल चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से देशभर के 8.11 करोड़ किसानों के लिए 15वीं किस्त के रूप में कुल 18.61 हजार करोड़ रुपए जारी किए थे। वहीं, 2019 से अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 15 किस्तों में 2.80 लाख करोड़ की धनराशि 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को दी जा चुकी है। अब 16वीं किस्त का किसानों को इंतजार है।

किसानों को अब मिलेंगे 12000 रुपए

पीएम मोदी ने 20 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनावों के तहत हनुमानगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की रकम दोगुनी करने की बात कही थी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि राजस्थान बीजेपी ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए 12,000 रुपए देने का फैसला किया है। अब राजस्थान में भाजपा की सरकार बन गई है। ऐसे में किसानों को 6000 की जगह 12000 रुपए सालाना मिलने की उम्मीद है।

भारतीय बाजार में इनका व्यावसायिक मूल्य बहुत अच्छा

मप्र सहित अन्य राज्यों में सफेद चंदन की खेती अब और आसान

भोपाल। जागत गांव हमार

चंदन का पेड़, जिसे भारत में चंदना के नाम से भी जाना जाता है, उसकी खेती थोड़ी कठिन मानी जाती है। इसका वानस्पतिक नाम सैंटालम एल्बम है. चंदन का पेड़ अलग-अलग प्रकार की मिट्टी में उगने में सक्षम होता है। यहां तक कि उथली चट्टानी मिट्टी में भी ये आसानी से उग जाता है, लेकिन जलभराव बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह बहुत अधिक तापमान सहन कर सकता है। भारतीय चंदन एक छोटा उष्णकटिबंधीय पेड़ है और चंदन के तेल का पारंपरिक स्रोत है। हिंदू धर्म जैसे कुछ धर्मों में इसे पवित्र माना जाता है और कुछ संस्कृतियां इसके सुगंधित गुणों को बहुत महत्व देती हैं। सफेद चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है. मार्केट में इसका रेट 8 से 10 हजार रुपए किलो है। जबकि विदेशों में एक किलो सफेद चंदन की कीमत 25 हजार किलो है। यानी कि इसके एक पेड़ से लाखों रुपए की कमाई की जा सकती है।

आजमाएं नर्सरी तकनीक

अगर आप सफेद चंदन की खेती करना चाहते हैं तो पहले से उपचारित बीजों को मिट्टी में बोया जाता है। फिर उसे पुआल से ढक दिया जाता है, जिसे अंकुर निकलने पर हटा दिया जाता है। जब अंकुर में 04 से 06 पत्तियां आ जाएं, तो पॉलिथीन बैग में डाल दें। उसके बाद आप इसे अपनी खेत में आसानी से लगा सकते हैं।

सफेद चंदन के उत्पाद

सफेद चंदन अपने औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसका उपयोग अगरबत्ती, कंठी माला, साबुन, खिलौने, परफ्यूम और हवन सामग्री बनाने में किया जाता है। चंदन से बने साबुन और परफ्यूम बहुत महंगा बिकता है। अगर किसान सफेद चंदन की खेती करते हैं तो बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं।

सफेद चंदन की खासियत

भारत में चंदन की कई किस्में उपलब्ध हैं। भारतीय चंदन और ऑस्ट्रेलियाई चंदन बहुत प्रसिद्ध हैं और बाजार में इनका व्यावसायिक मूल्य बहुत अच्छा है। चंदन की पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे के लिए भी किया जाता है। भारत में चंदन सबसे अधिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में उगाया जाता है। सफेद चंदन का उपयोग सामान्य सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, बुखार और मुंह और गले में खराश के इलाज के लिए किया जाता है। लकड़ी से प्राप्त तेल और लकड़ी का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है।

सांसद केपी यादव बोले-इन जिलों में लगे बायो रिफाइनरी

शिवपुरी, गुना-अशोकनगर में मक्का का बंपर उत्पादन

भोपाल। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले सांसद केपी यादव ने लोकसभा में मांग रखी है कि उनके संसदीय क्षेत्र में बायो रिफाइनरी स्थापित की जाए। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में नियम-377 के अधीन मामला उठाते हुए गुना-शिवपुरी-अशोकनगर सांसद केपी यादव ने लोकसभा क्षेत्र में मक्के के उत्पादन को देखते हुए सरकार से मांग की है कि यहां पर बायो रिफाइनरी स्थापित की जाए, जिससे क्षेत्र के युवा व किसान लाभान्वित हो सकें और रोजगार तथा विकास को नई गति प्राप्त हो। सांसद केपी यादव ने लोकसभा में अपनी मांग रखते हुए कहा कि गुना लोकसभा क्षेत्र में सात हजार हेक्टेयर में मक्के की बोवनी होती है। इस वर्ष गुना, अशोकनगर और शिवपुरी जिले में मक्के की रिकॉर्ड खेती हुई है। इसके अलवा प्रतिदिन 25 से 230 हजार क्विंटल मक्का मंडी में पहुंच रहा है। मक्के के उत्पादन और उपलब्धता को देखते हुए गुना लोकसभा क्षेत्र में बायो रिफाइनरी स्थापित करने की अपार संभावनाएं हैं।

एथेनॉल को प्रोत्साहन मिले - यादव ने कहा कि मेरा सरकार से निवेदन है कि इथेनॉल के उत्पादन हेतु मक्के की उपलब्धता को देखते हुए गुना लोकसभा में बायो रिफाइनरी की स्थापना के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिससे एथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहन मिले और हम 2025 तक 20 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को पूरा कर सकें।

एथेनॉल का उत्पादन एक अच्छा माध्यम

सांसद ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बायोफ्यूल जैसे एथेनॉल का उत्पादन एक अच्छा माध्यम है। क्योंकि इसका स्रोत किसानों द्वारा उगाई जाने वाली फैसले जैसे चावल, गन्ना और मक्का है। आज पूरे विश्व में एथेनॉल का 60 प्रतिशत उत्पादन मक्का से होता है। लेकिन भारत में अभी भी प्रमुख तौर पर गन्ने का इस्तेमाल होता है। इसकी प्रति हेक्टेयर खेती के लिए 1400 मिलीलीटर पानी इस्तेमाल होता है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)